गांवों और शहरों में आवासीय आवश्यकता संबंधी सर्वेक्षण

3473. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों और शहरों में आवासों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है ;

(ख) यदि हां, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की कितनी-कितनी आवश्यकता है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उठाय जाने वाल कदमों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम अरूणाचलमद्द) : (क) और (ख) सरकार द्वारा मकानों की कमी का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है । राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन आवास स्टाक संबंधी गणना के आंकडों के आधार पर समय-समय पर मकानों की कमी का अनुमान लगाता है । राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन के अनुमान के अनुसार 01-03-91 को 31 मिलियन रिहायशी एककों की कमी थी जिसमें से 10.4 मिलियन एकक शहरी क्षेत्रों में तथा 20.6 मिलियन एकक ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे ।

(ग) आवास राज्य विषय होने के नाते विभिन्न लक्षित वर्गों के लिए राज्य योजना प्रावधानों सहित अपने स्वयं के संसाधनों से आवास योजनायें तैयार तथा कार्यान्वित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों का है । राज्य सरकार आवास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए हुडको/एल०आईसी०/जी०आई०सी० से सांस्थानिक वित्त तथा आवास अभिकरणों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त लेने के लिए भी स्वतंत्र है । राष्ट्रीय आवास नीति में विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं जो मकानों के निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय/राज्य और पालिका स्तर पर किए जाने की आवश्यकता होगी । इनमें (i) आवास वित्त की उपलब्धता में वृद्धि (ii) आवास क्रिया-कलापों में कानूनी तथा अन्य अड़चनों को समाप्त करना (iii) विकसित भूमि अर्द्धसंचनात्मक सेवाओं और भवन निर्माण सामग्रियों आदि की अधिक आपूर्ति (iv) राज्य सरकारों द्वारा आठवीं योजना के अंतर्गत समयबद्ध कार्रवाई योजना को तैयार करना व कार्यान्वयन (v) प्राथमिकता वर्गों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना, पटरीवासियों के लिए रैन-बसेरे शहरी निर्धनों के लिए आश्रय सुधार आदि जैसी केंद्रीय योजनायें शामिल हैं ।

Encroachment of DDA land in Village Maidan Garhi, Delhi

3474. SHRI BHUBANESWAR KALITA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that though Khasra Nos. 1, 2, 3, 15,30,1008;/689/570/1, 1009/689/570/2, 572 and 554/2 measuring 51-10, 26-6, 10-6, 8-7, 6-01, 9-14, 7-18, 124-5 and 5 bighas respectively situated in the revenue estate of village Maidan Garhi are on record in the possession of Delhi Administration has been encroached;

(b) whether it is a fact that about 56 bighas of land out of Khasra No 569 Min. and about 20 bighas of land out of Khasra No: 687/570 in village Maidan Garhi is also under encroachment; and

(c) whether Government would take immediate action to remove the said encroachments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Illegal construction on Agricultural Land in Village Neb Sarai, Delhi

3475. SHRI BHUBANESWAR KALITA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government would stop forthwith the ongoing illegal construction activity on agricultural land in villages Neb Sarai, Saidul-ajaib, Chhattarpur and Devli in New Delhi; and

(b) whether Government would keep a constant vigil to check the illegal constructions activity in the entire area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir. Delhi Admn. reports that all efforts are being made to stop illegal construction activity in the said villages. Reports under Section 81 and 86A of the Delhi Land Reforms Act have been received and cases have been initiated against the alleged violators, the cases are sub-judice at present.

(b) Delhi Admn., reports that it is keeping a constant vigil and action is initiated under relevant legal provisions whenever such illegal activity is detected.

Development of roads in village Chhatarpur, Delhi

3476. SHRI BHUBANESWAR KALITA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state whether Government would develop all the Roads. Streets, paths and ways which have been made on tre agricultural land in village Chhattarpur, Neb Sarai, Saidul-ajaib, Maidan Garhi and Devli in New Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Municipal Corporation of Delhi has informed that the development works like roads, streets & parks etc. are provided in all rural villages within the boundary of Lal Dora. No such development works are carried out in unauthorised colonies/ Extensions developed on agricultural land outside Lal Dora.

बड़े शहरों में सरकारी कर्मचारियों को आवासों का आवंटन

3477. **श्री मूलचन्द मीणा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों को आवास के आवंटन में आरक्षण मिलता है, यदि हां, तो क्या उसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" में है तो उसके क्या कारण है;

(ग) आवास नीति का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार 1985 से आज तक आवंटित किए गए आवासों की सूची सभा पटल पर रखने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता

(घ) अलग आंकडे केंद्रीय रूप में नहीं रखे जा रहे है ।